बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 175 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 11 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब हर क्लास में होगा एक इंग्लिश मीडियम का सेक्शन

नई दिल्ली। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. साल 2025-26 से सभी सरकारी स्कूलों में हर क्लास में कम से कम एक अंग्रेजी मीडियम वाला सेक्शन जरूर होगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कई माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई करें, जिससे उन्हें आगे चलकर साइंस, टेक्नोलॉजी या अन्य ऊंची पढ़ाई में मदद मिल सके. बच्चों को इन सेक्शंस में रुचि और योग्यता के आधार पर दाखिला मिलेगा. स्कूलों को अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए सही किताबें और सामग्री देनी होगी. यह बदलाव स्कूल के नोटिसबोर्ड और सरकारी पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा. सरकार के अधिकारी यह जांच करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक सेक्शन को अंग्रेजी माध्यम के रूप में नामित किया जाना चाहिए.

एक राष्ट्र की शक्ति उसकी चिंतन की मौलिकता और मूल्यों की कालजयी प्रकृति में निहित होती है : उपराष्ट्रपति धनखड़

नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। आज उन्होंने कहा कि भारत का वैश्विक शक्ति के रूप में उदय उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक गरिमा के उत्थान के साथ होना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा उदय ही टिकाऊ होता है और हमारी परंपराओं के अनुकूल होता है। एक राष्ट्र की शक्ति उसकी सोच की मौलिकता, मूल्यों की कालातीतता और बौद्धिक परंपरा की दृढ़ता में निहित होती है। यहीं सॉफ्ट पावर (सांस्कृतिक प्रभाव) है जो दीर्घकालिक होता है और आज के विश्व में अत्यंत प्रभावशाली है। औपनिवेशिक मानसिकता से परे भारत की पहचान को पुनः स्थापित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, भारत केवल 20वीं सदी के मध्य में बना राजनीतिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह एक सतत सभ्यता है - चेतना, जिज्ञासा और ज्ञान की प्रवाहित नदी। देशज ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से दरकिनार किए जाने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, देशज विचारों को केवल आदिम और पिछड़ेपन का प्रतीक मानकर खारिज करना केवल एक व्याख्यात्मक भूल नहीं थी - यह मिटाने, नष्ट करने और विकृत करने की वास्तुकला थी। और अधिक दुखद यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी यह एकतरफा स्मरण चलता रहा। पश्चिमी अवधारणाओं को सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। साफ़ शब्दों में कहें तो– असत्य को सत्य के रूप में सजाया गया। उन्होंने सवाल किया, जो हमारी बुनियादी प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वह तो विचार के दायरे में भी नहीं थी। हम अपनी मूल मान्यताओं को कैसे भूल सकते हैं? भारत की बौद्धिक यात्रा में ऐतिहासिक व्यवधानों को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, इस्लामी आक्रमण ने भारतीय विद्या परंपरा में पहला व्यवधान डाला - जहां समावेशन की बजाय तिरस्कार और विध्वंस का मार्ग अपनाया गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद दूसरा व्यवधान लेकर आया–जिसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली को पंगु बना दिया गया, उसकी दिशा बदल दी गई। विद्या के केंद्रों का उद्देश्य बदल गया, दिशा भ्रमित हो

गई। त्रुटियों की भूमि बाबुओं की भूमि बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को बाउन बाबू चाहिए थे, राष्ट्र को विचारक। उन्होंने कहा, हमने सोचना, चिंतन करना, लेखन और दर्शन करना छोड़ दिया। हमने रटना, दोहराना और निगलना शुरू कर दिया। ग्रेड्स (अंक) ने चिंतनशील सोच का स्थान ले लिया। भारतीय विद्या परंपरा और उससे जुड़े संस्थानों को सुनियोजित ढंग से नष्ट किया गया। भारतीय ज्ञान प्रणाली सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, जब यूरोप की यूनिवर्सिटियां भी अस्तित्व में नहीं थीं, तब भारत की विश्वविख्यात विश्वविद्यालयें– तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और ओदंतपुरी–ज्ञान के महान केंद्र थीं। इनकी विशाल पुस्तकालयों में हजारों पांडुलिपियाँ थीं। उन्होंने बताया कि ये वैश्विक विश्वविद्यालय थे, जहां कोरिया, चीन, तिब्बत और फारस जैसे देशों से भी विद्यार्थी आते थे। ये ऐसे स्थल थे जहां विश्व की बुद्धिमत्ता भारत की आत्मा से आलिंगन करती थी। उपराष्ट्रपति ने ज्ञान को व्यापक रूप में समझने का आह्वान करते हुए कहा, ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं होता–यह समुदायों में, परंपराओं में, और पीढ़ियों से हस्तांतरित अनुभव में भी जीवित रहता है। उन्होंने बल दिया कि एक सच्ची भारतीय ज्ञान प्रणाली को शोध में ग्रंथ और अनुभव–दोनों का समान महत्व देना होगा। संदर्भ और सजीवता से ही सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। व्यावहारिक कदमों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, हमें तत्काल कार्यवाही की ओर ध्यान देना होगा। संस्कृत, तमिल, पाली, प्राकृत आदि सभी क्लासिकल भाषाओं के ग्रंथों के डिजिटलीकरण की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए। उन्होंने जोड़ा, ये सामग्री शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ होनी चाहिए। साथ ही, युवाओं को शोध की ठोस विधियों से लैस करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जरूरी हैं–जिसमें दर्शन, गणना, नृविज्ञान और तुलनात्मक अध्ययन का समावेश हो। उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का उद्धरण देते हुए कहा, यदि मुझसे पूछा जाए कि संसार के किस भाग में मानव मस्तिष्क ने अपने कुछ सबसे उत्कृष्ट विचारों को जन्म दिया है, जीवन के गंभीरतम प्रश्नों पर सबसे गहरा विचार किया है और उनका उत्तर खोजने का प्रयास किया है- तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। उन्होंने कहा, मित्रों, यह एक सनातन सत्य का उद्घोष था। परंपरा और नवाचार के बीच संबंध की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, अतीत की ज्ञान-परंपरा नवाचार की विरोधी नहीं, प्रेरक होती है। अध्यात्म और वैज्ञानिकता साथ-साथ चल सकते हैं–पर इसके लिए यह जानना होगा कि अध्यात्म क्या है। उन्होंने कहा, ऋग्वेद के ब्रह्मांड संबंधी मंत्र आज के खगोल-भौतिकी के युग में फिर से प्रासंगिक हो सकते हैं। चरक संहिता को आज की वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य नैतिकता की बहसों के साथ पढ़ा जा सकता है। उन्होंने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा, आज हम एक विभाजित और संघर्षपूर्ण विश्व से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत की वह ज्ञान परंपरा–जो आत्मा और जगत, कर्तव्य और परिणाम, मन और पदार्थ के बीच संबंधों पर हजारों वर्षों से चिंतन करती रही है–एक समावेशी, दीर्घकालिक समाधान के रूप में पुनः प्रासंगिक हो उठती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, जेएनयू की कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलीपुडी पंडित, प्रो. एम.एस. चैत्र (आईकेएसएचए के निदेशक), प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय टोली सदस्य, तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

बड़े भाई ने खर्चा देना बंद किया तो गला रेतकर कर डाली हत्या, कमरे से आ रही थी बदबू

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बड़े भाई ने छोटे को खर्चा देना बंद कर दिया तो उसने गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी कमरे पर ताला लगाकर फरार हो गया। 6 जुलाई को सड़ी-गली हालत में इदरीश (35) का शव बरामद हुआ। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान मृतक का मोबाइल गायब मिला। पुलिस ने सोसाइटी की कैमरे की फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान इरशाद आलम (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू और इदरीश का मोबाइल बरामद कर लिया है। उत्तर-पूर्वी जिला के पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि 6 जुलाई को न्यू उस्मानपुर इलाके में कुछ लोगों ने एक कमरे से दुर्गंध आने की सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का ताला बंद था। अंदर तेज दुर्गंध थी। पुलिस ने ताला तोड़ा तो अंदर खून से लथपथ इदरीश का शव मिला। शव तीन-चार दिन पुराना लग रहा था। उसका गला रेता हुआ था। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह मूलरूप से किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं। इसका भाई अपना काम करता था। भाई ने रोजाना इरशाद को काम के बदले 500 रुपये और 100 रुपये खर्चा देने को बोला था। कुछ दिन तो भाई ने रुपये दिए, बाद में बंद कर दिए। रुपये मांगने पर उसका भाई से झगड़ा हो गया। इसी वजह से उसने चार जुलाई को भाई की हत्या की।

मणिपुर में बेघर लोगों के लिए घर बनाने का टेंडर नहीं निकला, कांग्रेस ने आरोप के साथ जांच की मांग की

नई दिल्ली। मणिपुर में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने राय सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बेघर लोगों के लिए बनाए जा रहे प्री-फैब्रिकेटेड (तैयार ढांचे वाले) घरों के निर्माण में कोई टेंडर (निविदा) नहीं निकाली गई। कांग्रेस ने इस मामले की पूरी जांच कराने की मांग की है। राय कांग्रेस अध्यक्ष केराम मेघचंद्र ने बुधवार को विष्णुपुर जिले में दो निर्माण स्थलों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों जगहों पर बिना किसी सरकारी आदेश या टेंडर के ही निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, यह काम आधिकारिक रूप से नहीं हो रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि जांच की जाए कि बिना टेंडर के ये घर कैसे बनाए जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सैकड़ों करोड़ रुपये की गड़बड़ी हो रही है। केराम मेघचंद्र, जो वांगखेम विधानसभा सीट से विधायक भी हैं, ने कहा कि राय और केंद्र सरकार दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित लोगों को जो भी आर्थिक सहायता दी जा रही है, वह सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाए। किसी बिचौलिये के जरिए पैसे न दिए जाएं। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार एक तय समयसीमा घोषित करे, जिसके भीतर सभी विस्थापित लोगों को उनके मूल घरों में सुरक्षित वापसी कराई जा सके। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को एक ज्ञापन भी सौंपा है। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद हजारों लोग बेघर हो गए थे। इनके लिए सरकार ने कई जिलों में अस्थायी प्री-फैब्रिकेटेड घर बनवाने की योजना शुरू की है, लेकिन कांग्रेस अब इस योजना में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा रही है।

दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग, कितनी थी तीव्रता?

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. इस दौरान लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए. अभी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. दिल्ली-एनसीआर के इलाकों के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए. भूकंप 4.4 तीव्रता का था. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था. झज्जर में भारतीय समयानुसार सुबह 9:04 बजे रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया. राज्य के जींद में भी भूकंप के तेज झटके लगे. बहादुरगढ़ में भी भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस हुए. इसके अलावा सोनीपत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुले स्थान में आ गए. भूकंप के झटकों से मकान हिलने लगे. लोगों ने तत्काल अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली और कुछ समय तक बाहर ही रुके रहे. भूकंप का असर खासकर दिल्ली और नोएडा की हाईराइज सोसायटी में रहने वालों पर ज्यादा पड़ा, जहां लोग अत्यधिक घबराहट का सामना कर रहे थे. इससे पहले 17 फरवरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के मध्यम झटके महसूस किए गए थे. भूकंप सुबह 5.37 बजे के करीब आया था. झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगीं और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे. पेड़ों पर बैठे पक्षी भी तेज आवाज के साथ इधर-उधर उड़ने लगे. राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 थी. इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से पांच किलोमीटर की गहराई पर था. यह 28.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.16 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था. गहराई कम होने और केंद्र दिल्ली में होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में इसे ज्यादा महसूस किया गया. भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी धरती की सतह मुख्य रूप से सात बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है. ये प्लेट्स लगातार हरकत करती रहती हैं और अक्सर आपस में टकराती हैं. इस टक्कर के परिणामस्वरूप प्लेट्स के कोने मुड़ सकते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण वे टूट भी सकती हैं. ऐसे में, नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर फैलने का रास्ता खोजती है और यही ऊर्जा जब जमीन के अंदर से बाहर आती है, तो भूकंप आता है.

दिल्ली में बारिश से जलभराव और जाम की मार, आप ने बीजेपी को घेरा

नई दिल्ली।

दिल्ली में कई दिनों के बाद हुई भारी बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर के कई हिस्सों में जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. बुधवार (9 जुलाई) की बारिश लंबे समय तक हुई जिससे नेहरू प्लेस, अरबिंदो मार्ग, लाजपत नगर, अक्षरधाम, आश्रम, आईटीओ और शादीपुर जैसे इलाकों में पानी भर गया, इस वजह से आवाजाही बाधित रही. नजफगढ़ में 60 मिमी, आया नगर में 50.5 मिमी और प्रगति मैदान में 37 मिमी तक बारिश दर्ज की गई. वहीं, सफदरजंग वेधशाला में केवल 1.4 मिमी वर्षा हुई. बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग के कंट्रोल रूम को 29 शिकायतें मिलीं, जिनमें झिलमिल अंडरपास, लोनी गोल चक्कर और यमुना विहार शामिल हैं. मौसम विभाग ने दोपहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर रेड अलर्ट कर दिया गया. पीटीआई के अनुसार, विभाग ने तेज बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है और लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी गई है.मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जलजमाव के कारण राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज रही. आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने वीडियो साझा करते हुए बीजेपी पर तंज कसा, चार इंजन की सरकार, चारों खटारा निकले. उन्होंने कहा कि पटपड़गंज से लेकर लुटियंस दिल्ली तक सड़कों पर जलभराव की स्थिति भयावह है. दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भी बीजेपी सरकार और सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा, शालीमार बाग की विधायक ने अपने क्षेत्र को स्विमिंग पूल बना दिया. इस मुद्दे पर दिल्ली में सियासत भी उतनी ही तेज हो गई है जितनी बारिश की धारें.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम सैंपल की अनावश्यक जांच पर जताई चिंता, 3 महीने में दिशा-निर्देश बनाने को कहा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह पोस्टमार्टम के बाद सैंपल को उनको ओर से संचालित फॉरेंसिक साइंस लैब भेजने की प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक तय करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार करे. हाईकोर्ट ने कहा कि जरुरत से ज्यादा और मेडिकल रूप से गैरजरूरी रेफरल सैम्पल प्रणाली पर अत्यधिक बोझ डाल रहे हैं, जिससे आपराधिक जांच की गति धीमी हो रही है. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन में एमडी कर रहे डॉ. सुभाष विजयन की याचिका पर सुनवाई के दौरान की. कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए संबंधित अधिकारियों को तीन महीने का समय दिया है. कोर्ट में दाखिल याचिका में डॉ. विजयन ने दावा किया कि नैदानिक नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए बिना विवेक के भेजा जा रहा है, जबकि कई मामलों में न तो मेडिकल सबूत होते हैं और न ही कानूनी आवश्यकता. याचिकाकर्ता ने बताया कि कई डॉक्टर यह सोचकर सैंपल भेज देते हैं कि यदि बाद में कोई कानूनी सवाल उठे, तो उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए, भले ही मामला पूरी तरह स्पष्ट हो और उसमें किसी साजिश की आशंका न हो. डॉ. विजयन ने याचिका में कहा कि यह डर और सतर्कता डॉक्टरों को हर मामले में सैंपल भेजने को मजबूर कर रही है.

, जबकि कई बार पुलिस भी कह देती है कि लैब जांच की आवश्यकता नहीं है, फिर भी डॉक्टर ऐसा करते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि हमारे देश के अधिकतर डॉक्टर कोर्ट और कानूनी प्रक्रिया से डरते हैं. संभावित कानूनी परेशानी से बचने के लिए वे हर केस में नमूने भेज देते हैं, जिससे लैब पर बेवजह दबाव पड़ता है. याचिका में यह भी कहा गया कि इस प्रथा के चलते फॉरेंसिक लैब की पहले से सीमित क्षमता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिससे अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी होती है और मृतकों के परिजनों को भी अनावश्यक मानसिक तनाव झेलना पड़ता है.

शशि थरूर ने लोकतंत्र काले अध्याय को किया याद, कहा- आपातकाल एक सबक है

नई दिल्ली।

आपातकाल की तीखी आलोचना करते हुए एक लेख में, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि स्वतंत्रता का हनन कैसे होता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे दुनिया मानवाधिकारों के हनन की भयावह सूची से अनजान रही। प्रोजेक्ट सिंडिकेट द्वारा प्रकाशित इस लेख में, थरूर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सत्तावादी दृष्टिकोण ने सार्वजनिक जीवन को भय और दमन की स्थिति में धकेल दिया। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आज का भारत 1975 का भारत नहीं है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि आपातकाल को भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में ही याद नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इससे मिले सबक को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए और लोकतंत्र के प्रहरियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मलयालम दैनिक 'दीपिका'

में बृहस्पतिवार को आपातकाल पर प्रकाशित एक लेख में कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले दौर को याद किया और कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरतापूर्ण कृत्यों में बदल जाते हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता था। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने लिखा, ''इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया जो इसका एक संगीन उदाहरण बन गया। पिछड़े ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और बल का इस्तेमाल किया गया। नयी दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त कर उनका सफाया कर दिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए। उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया।'' उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए, यह एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। थरूर ने कहा, ''यह सभी को हमेशा याद दिलाता रहे।'' थरूर के अनुसार, आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। उन्होंने कहा, ''हम ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा विकसित और कई मायनों में ज्यादा मजबूत लोकतंत्र हैं। फिर भी, आपातकाल के सबक चिंताजनक रूप से प्रासंगिक बने हुए हैं।'' थरूर ने चेतावनी दी कि सत्ता को केंद्रीकृत करने, असहमति को दबाने और संवैधानिक रक्षात्मक उपायों को दरकिनार करने की प्रवृत्ति विभिन्न रूपों में फिर से उभर सकती है। उन्होंने कहा, ''अक्सर ऐसी प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय हित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जा सकता है। इस लिहाज से आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के प्रहरियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रेन से गिरकर मौत पर रेलवे देगा मुआवजा, ट्रिब्यूनल का आदेश पलटा

नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज जैन ने अपने अहम फैसले में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया है कि वह ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को निर्धारित नियमों के तहत मुआवजा प्रदान करे. यह मामला अमरपाली एक्सप्रेस से जुड़ा है, जिसमें मृतक नई दिल्ली से सिवान जंक्शन जा रहा था. खुरजा स्टेशन पर ट्रेन में पानी की सुविधा न होने के कारण वह नीचे उतरा था, और पानी लेकर वापस उसी ट्रेन में चढ़ते समय भीड़ के कारण गिर पड़ा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. रेलवे ने इस दावे को नकारते हुए कहा था कि मृतक खुरजा स्टेशन पर पटरियों को पार कर रहा था और दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हुई. ट्रिब्यूनल ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था कि मृतक ने गलत दिशा से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी, जो उसकी गलती थी. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि यह विशेष महत्व नहीं रखता कि मृतक ने ट्रेन में गलत दिशा से चढ़ने की कोशिश की, जब यह साफ हो चुका है कि वह ट्रेन में दोबारा सवार हो गया था और उसके बाद गिरा. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रेन के उसी कोच में यात्रा कर रहे एक गवाह नसीम की गवाही को भी बेहद अहम माना है, जिसने यह साफ किया कि मृतक को किसी दूसरी ट्रेन ने नहीं मारा. इसके अलावा, जिस ट्रेन से टकराने का आरोप लगाया गया था, उसके लोको पायलट की गवाही भी मृतक के दोबारा चढ़ने और गिरने की बात को मजबूत करती है. कोर्ट ने कहा कि यह एक अप्रत्याशित दुर्घटना थी और मृतक ट्रेन में पहले से यात्रा कर रहा था. इसलिए, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को 'रेलवे दुर्घटनाएं और आकस्मिक घटनाएं (मुआवजा) नियम 1990' के तहत निर्धारित मुआवजा 8 हफ्तों के भीतर देना होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के आदेश को पलटते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए कहा है.

दुनिया भर में सैन्य ख़र्च में बढ़ोतरी के मायने

प्रभात पटनायक

दुनिया भर में फौजी खर्चों में उछाल आया हुआ है, जिसकी अगुआई यूरोप में आया उछाल कर रहा है। बेशक, फौजी खर्चों के आकलन अलग-अलग हैं, जो इस पर निर्भर करते हैं कि किसी गिनती में क्या-क्या शामिल किया जा रहा है। बहरहाल, हम यहां अपने विश्लेषण के लिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI या सिपरी) के आंकड़ों को लेंगे। सिपरी के अनुसार, वैसे तो लगातार पिछले दस साल से साल दर साल वास्तविक फौजी खर्चों में बढ़ोतरी होती रही है, 2024 में खर्च में यह बढ़ोतरी, इससे एक साल के पहले के मुकाबले 9.4 फीसद रही थी, जो कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से, इस खर्च में सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी थी। 2024 में कुल वैश्विक फौजी खर्च 27.18 खरब डालर रहा था। हम इस उछाल के पीछे के दो कारणों का अनुमान लगा सकते हैं। पहला तो यह कि अमरीका के नेतृत्व में उन्नत पूंजीवादी दुनिया के साम्राज्य को लगातार बढ़ती हुई चुनौती का और खासतौर पर अमरीका में आवास के बुलबुले के बैठने के बाद से नव-उदारवादी पूंजीवाद के संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा कारण इस तथ्य में निहित है कि अमरीका अब इस साम्राज्य को बरकरार रखने पर आने वाले सैन्य खर्चे के मुख्य हिस्से की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं है बल्कि वह चाहता है कि उसके यूरोपीय साझीदार भी, इस बोझ का एक हिस्सा संभालें। इन कारणों से साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा सैन्य खर्चों में आक्रामक बढ़ोतरी किए जाने से, अन्य देशों पर भी इसके लिए दबाव पड़ रहा है कि वास्तविक मूल्य में अपने सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी करें, ताकि साम्राज्यवादी ताकतें उन्हें कुचल नहीं दें। इन दोनों कारणों पर दो-दो शब्द कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। इस संकट के बाद से अनेक देशों ने, जो उस संकट से पहले अपने भुगतान संतुलन में किसी गंभीर चालू खाता घाटे का सामना नहीं कर रहे थे या जो घाटे में तो थे, लेकिन जिनके घाटों का वित्तीय प्रवाहों से वित्त पोषण किया जा सकता था, खुद को इस संकट के बाद से मुश्किल में फंसा पाया था। और महामारी के आने के बाद हालात उनके लिए बदतरीन हो गए। उनके निर्यात बाजार सिकुड़ने के साथ, उनके चालू खाता घाटे बढ़ गए। और इन देशों को अर्थव्यवस्थाओं से पैसा निकालने में मुश्किलें आने की आशंकाओं से, इन अर्थव्यवस्थाओं में वित्त का प्रवाह सूख गया। वे ऋण के संकट में फंस गए। ऐसा ही हश्र, महामारी के बाद और तेजी के साथ कई देशों के साथ हुआ। इन घटनाक्रमों ने इस नव-उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति मोहभंग पैदा किया, जिसे अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी ताकतों ने दुनिया पर थोपा था। इसी दौरान चीन ने, जिसने उल्लेखनीय रूप से ऊंची वृद्धि दरों का प्रदर्शन किया था, जो कम से कम शुरूआत में तो खुद महानगरीय पूंजी के ही तत्वावधान में, पूंजी के महानगरों से आर्थिक गतिविधियों के स्थानांतरण से उत्प्रेरित रहा था, और जिसके पास तगड़ी चालू खाता बचतें थीं, आगे बढ़कर ऐसे संकट के शिकार देशों को और कुछ इतने तात्कालिक रूप से संकट का सामना नहीं भी कर रहे देशों को भी कुछ राहत मुहैया करायी थी। इससे साम्राज्यवाद के प्रभुत्व के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जिसके खिलाफ साम्राज्यवाद सैन्य हस्तक्षेप की अपनी क्षमता को मजबूत करना चाहता है। इसके साथ ही साथ अमरीका अपने सैन्य खर्च का कुछ हिस्सा, संकट की पृष्ठभूमि में अन्य साम्राज्यवादी देशों पर डालना चाहता है। यह उसी तरह है जैसे अमरीका ''पड़ोसी जाए भाड़ में'' की नीति के जरिए, अपनी अर्थव्यवस्था पर संकट के प्रभावों को परे छिटकने के लिए, टैरिफों का सहारा ले रहा है। इस तरह उसका सैन्य खर्च का एक हिस्सा दूसरों के सिर पर डालना, समग्रता में साम्राज्यवादी दुनिया के सैन्य खर्च को बढ़ा रहा है क्योंकि यूरोप को, जो कम से कम आर्थिक रूप से तो अमरीका की सैन्य छतरी के नीचे रह रहा था, अब अपने बूते पर कहीं ज्यादा सैनिक खर्चा करना पड़ रहा है। यूरोपीय सरकारें, रूसी हमले के खतरे के नाम पर, अपने इस बढ़ते हुए सैनिक खर्च को सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन, यह दावा छानबीन में नहीं टिक पाता है। सच्चाई यह है कि सोवियत संघ के पराभव के समय, मिखाइल गोर्बाचोव से क्लिंटन प्रशासन द्वारा इसका वादा किए जाने के बावजूद कि पूर्व की ओर नाटो का विस्तार नहीं किया जाएगा, इस दौरान ऐन रूस की सीमाओं तक उसका विस्तार कर दिया गया है। और यूक्रेन में, विक्टर यानुकोविच की निर्वाचित सरकार के खिलाफ अमरीका द्वारा तख्तापलट कराया गया, जिसमें एक फासिस्ट निजाम को सत्ता में बैठा दिया गया, जिसमें युद्ध के दौर में नात्सियों के सहयोगी रहे स्तेपान बंडेरा के अनुयाई शामिल थे। और इस निजाम ने रूसी-भाषी अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमनचक्र छेड़ दिया और नाटो की सदस्यता की मांग शुरू कर दी। रूस को तो इस खतरे का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए, यूरोप के खिलाफ रूसी हमले की सारी बातें, शुद्ध साम्राज्यवादी प्रचार हैं। यह उल्लेखनीय है कि 2024 में रूस का कुल सैन्य खर्च 149 अरब डालर था, जबकि नाटो के यूरोपीय सदस्यों का कुल सैन्य खर्च 454 अरब डालर था यानी रूस के कुल खर्च से तीन गुने से भी ज्यादा। और यह तब था जबकि रूस इस समय वास्तव में युद्ध में लगा हुआ है। इसलिए, रूस से तीन गुना ज्यादा सैन्य खर्चा करने के लिए रूसी खतरे का बहाना बनाना, एक हास्यास्पद धोखाधड़ी है। यूरोपीय सैन्य खर्च उसके अपने समीकरणों से संचालित हैं, जिनका संबंध साम्राज्यवादी व्यवस्था के बनाए रखे जाने से है। इस संदर्भ में जर्मनी के सैन्य खर्च में बढ़ोतरी खासतौर पर चिंताजनक है। जर्मनी के इस खर्च में पिछले साल 28 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति से लेकर, जहां जर्मनी को दोबारा अपना शस्त्रीकरण करने की इजाजत ही नहीं थी, वर्तमान अवस्था तक जहां 2024 में वह यूरोप में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्चा करने वाला देश बन गया, बहुत भारी बदलाव आ चुका है। जर्मनी के नात्सी अतीत को देखते हुए, जिसके पुनरावर्तन के लक्षण दिखाई देने लगे हैं और उसके युद्धप्रियता के खासतौर पर बदनाम इतिहास को देखते हुए, यह एक ऐसा घटनाविकास है जो बहुत ही गंभीर दुष्परिणामों को समेटे हुए है। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, इस प्रकार है- साम्राज्यवादी दुनिया में सैन्य खर्चों में इस बढ़ोतरी और इसे और भी बढ़ाने की इन देशों की घोषित प्रतिबद्धता को देखते हुए, इन सैन्य खर्चों का वित्त पोषण कैसे होने जा रहा है? जहां राजकोषीय घाटे में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होना तय है, कल्याणकारी खर्चों में कटौतियां किया जाना तय है। ऐसा खासतौर पर इसलिए है कि इस समय के पूंजीवादी सरकारों के खयाल के हिसाब से, पूंजीपतियों को कर रियायतें देना ही, अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करने का मुख्य उपाय है। यह डोनाल्ड ट्रम्प के राजकोषीय विधेयक पर एक नजर डालने से साफ हो जाता है। उनके इस एजेंडा को उनके कथित ''बिग ब्यूटीफुल बिल'' में सूत्रबद्ध किया गया है, जिसे हाल ही में अमरीकी कांग्रेस ने पारित कर दिया है और जिसके सीनेट द्वारा अनुमोदन का इंतजार है। इस विधेयक के अनुसार, जहां अगले दस साल में 37.6 खरब डालर की कर रियायतें दी जा रही होंगी, खर्चों में कुल 13 खरब डालर की कटौती की जा रही होगी, जिससे सरकार के सकल ऋण में 25 खरब डालर की बढ़ोतरी होगी (जिसमें ब्याज का हिस्सा शामिल नहीं है)। इस विधेयक के अंतर्गत कर रियायतें प्रकटतः तो आबादी के सभी तबकों को दी जा रही होंगी, लेकिन कर तथा व्यय प्रस्तावों को जोड़कर देखा जाए तो उसके सबसे बड़े लाभार्थी अमीर ही होंगे, जबकि गरीबों की दशा में शुद्ध गिरावट आएगी। वास्तव में, सबसे ऊपर के पायदान पर आने वाली 10 फीसद आबादी के पारिवारिक संसाधनों में आने वाले वर्षों में शुद्ध बढ़ोतरी होगी, जबकि सबसे निचले पायदान पर आने वाली 10 फीसद आबादी के पारिवारिक संसाधनों में शुद्ध गिरावट आएगी। यह गिरावट मुख्य रूप से मैडिकेड तक उनकी पहुंच घटने और स्वास्थ्य बीमा के लिए वसूली बढ़ने के चलते आ रही होगी। जहां अमरीकी कांग्रेस ने महज एक वोट के बहुमत से उक्त विधेयक को पारित किया है और जहां सीनेट में क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है, वहीं वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी किस हद तक इस विधेयक को मंजूर करेगी, वह एक पूरी तरह से अलग ही मामला है और अभी भी स्पष्ट नहीं है। ब्रिटेन में लिज ट्रस की सरकार ने पूंजीपतियों को कर रियायतें देने के लिए, राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया था, लेकिन राजकोषीय घाटे में यह बढ़ोतरी तक वित्तीय पूंजी को मंजूर नहीं हुई थी।

दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी हीरोइन

वैसे तो सिंगर दिलजीत दोसांझ विवादों के आदी हैं। कई बार हमारे आर्टिस्ट लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी विवाद खड़ा कर देते हैं पर उन्हें लेकर जो ताज़ा विवाद है वह तो फ़िज़ूल लगता है। मामला उनकी फ़िल्म 'सरदार जी3' से सम्बन्धित है, क्योंकि उस फ़िल्म में उनके साथ पाकिस्तानी हीरोइन हानिया आमीर काम कर रही है। इसी पर दिलजीत की बड़ी आलोचना की गई। मांग की गई कि उन्हें बार्डर-2 से निकाल दिया जाए। फैडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने इम्पलॉईज़ एसोसिएशन ने तो और बढ़ते हुए मांग की है कि दिलजीत दोसांझ की नागरिकता रद्द कर दी जाए। शिकायत यह है कि दिलजीत दुश्मन देश की हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं, जो पहलगाम की घटना के बाद अस्वीकार्य है। दिलजीत की देशभक्ति पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह मांग भी की गई कि दिलजीत दोसांझ के म्यूज़िक पर बैन लगा दिया जाए। फ़िल्म सरदार जी 3 की शूटिंग फरवरी में पहलगाम की घटना से दो महीने पहले हुई थी। दिलजीत बता चुके हैं कि फ़िल्म में कलाकारों का चुनाव निर्माता -निर्देशक करते हैं। उन्हें तो केवल बताया गया कि तुम ने हानिया आमीर के साथ काम करना है। अतीत में भी फवाद खान और महीरा खान जैसे कई पाकिस्तानी एक्टर हमारी फ़िल्मों में काम कर चुके हैं। निर्माता ने लोगों की उत्तेजित भावनाओं को देखते हुए फ़िल्म को भारत में रिलीज़ न करने का फ़ैसला किया है। पहले भी कई बार फ़िल्मों की रिलीज़ इसलिए रोकनी पड़ी थी क्योंकि किसी न किसी की धार्मिक या देशभक्ति की भावना 'आहत हो रही थी'। हम इतने असुरक्षित क्यों हैं किसी फ़िल्म या किसी कामेडियन के शो से आहत हो जाते हैं ? दिलजीत दोसांझ के इस तर्क पर कि यह फ़िल्म पहलगाम से पहले बनी थी पर एक उत्तेजित एंकर (हमारे एंकर उस तरह संयम और मर्यादा में क्यों नहीं रह सकते जैसे बीबीसी या सीएनएन या अल जज़ीरा के एंकर रहते है? हर मामले पर चीखने-चिल्लाने या लड़ने की क्या ज़रूरत है?) कह रहे थे कि पहलगाम से पहले भी तो बहुत कुछ हुआ। मुम्बई, उरी, पठानकोट,पुलवामा बहुत कुछ हुआ फिर पाकिस्तानी हीरोइन को क्यों लिया गया? पर फरवरी में हमने पाकिस्तान के साथ दुबई में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैच भी खेला था। उस क्रिकेट की जीत पर सारे देश ने खुशी मनाई थी। तो क्या बीसीसीआई पर भी बैन लगना चाहिए? उसके पदाधिकारियों की देश भक्ति पर सवाल लगने चाहिए आखिर उन्होंने टीम को 'दुश्मन' की टीम के साथ खेलने दिया? कई टीवी चैनल तो पैसे देकर पाकिस्तानियों को अपने शो पर बुलाते रहे हैं ताकि टीआरपी बढ़ सके। इनके बारे क्या करना है? दिलजीत दोसांझ बहुत मशहूर आर्टिस्ट है। 'चमकीला' जैसी फ़िल्मों में वह बढ़िया रोल कर चुके हैं। विदेशों में उनके शो सोल्ड आउट जाते हैं। दर्शकों में पाकिस्तानियों की भी बड़ी संख्या होती है।

दोनों तरफ़ के पंजाबी भरे होते हैं। भाजपा के नेता और कलाकार हॉबी धालीवाल ने तो दिलजीत दोसांझ को 'पंजाबी कलचर' का आइकॉन बताया है। उनका यह सही तर्क है कि केवल दिलजीत ही नहीं फ़िल्म में और बहुत से दूसरे कलाकार भी हैं। दिलजीत दोसांझ पर जो तूफ़ान खड़ा किया गया उसके पीछे प्रोफेशनल स्पर्धा भी लगती है। बहुत से दूसरे पंजाबी कलाकार, जो खुद पाकिस्तान जा चुके हैं या पाकिस्तानियों के साथ काम कर चुके हैं, आज दिलजीत दोसांझ की आलोचना कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर कई बार मर्यादा की रेखा पार कर चुके हैं। ड्रग्स से लेकर हथियारों की प्रदर्शनी कर चुके हैं। नशे का गुणगान कर चुके हैं। कोई एक ही दोषी नहीं है। सच्चाई है कि पाकिस्तान को लेकर हमारे समाज और सरकार दोनों में विरोधाभास ही नहीं, दोगलापन भी है। मेरे एक मित्र हैं। उन्होंने आजकल की भाषा में 'भक्त' भी कहा जा सकता है। वह पाकिस्तानी हीरोइन के साथ काम करने के लिए दिलजीत दोसांझ पर पाबंदी चाहते हैं। मैंने पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो तो जवाब मिला, मैडम के साथ बैठ कर पाकिस्तानी सीरियल देख रहे हैं। उस वक्त उन्हें न पुलवामा याद आया और न ही पहलगाम। यह कड़वी सच्चाई है कि हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग विशेष तौर पर उत्तर भारत में, पाक सीरियल का दीवाना है। सांझी भाषा और संस्कृति और यूट्यूब जैसे चैनलों ने इन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया है। 'सुनो चंदा','मेरे हम सफ़र','तेरे बिना', 'कभी मैं कभी तुम', जैसे सीरियल अपनी कहानी के कारण 'भक्त' परिवारों में बहुत लोकप्रिय है। इस दौरान कई आतंकी घटनाएं हुईं पर उनकी देशभक्ति उन्हें पाकिस्तानी सीरियल देखने से नहीं रोक सकी। वह घर के अंदर बैठ कर पाकिस्तानी सीरियल देख सकते हैं, पर दिलजीत दोसांझ जिसका फ़िल्म निर्माण से कोई सम्बंध नहीं, वह तो दोषी है! उस पर पाबंदी लगनी चाहिए! यही विरोधाभास सरकार की नीति में नज़र आता है। पहले पाकिस्तानी सेलेब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगा दिया। फिर खोल दिया पर सोशल मीडिया पर उठे तूफ़ान के बाद फिर लगा दिया अर्थात् सरकार समझ नहीं पा रही कि पाकिस्तानियों का क्या किया जाए? एक तरफ़ सोच है कि चीन के साथ उस देश की बढ़ती निकटता को देखते हुए पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने का कुछ प्रयास होना चाहिए पर दूसरी तरफ़ जिस रंग को उत्तेजित कर चुके हैं। उसे भी संतुष्ट रखना है। राष्ट्रीय आइकॉन नीरज चोपड़ा को माफ़ी मांगनी पड़ी कि बैंगलुरु में हो रहे एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम को आमंत्रित किया था। यह निमंत्रण, जो उन्होंने रद्द कर दिया, पहलगाम से पहले दिया गया था। पर ऐसे लोग भी थे जो नीरज चोपड़ा की देशभक्ति पर सवाल उठाने लगे थे। उनके परिवार को ट्रोल किया गया। कैसा पागलपन है? एक टीवी बहस में एंकर ज़ोर शोर से वकालत कर रहे थे कि पाकिस्तान का फ़िल्मों और खेलों में बॉयकॉट किया जाना चाहिए। उन्होंने रंग भेद नीति के दौरान दक्षिण अफ्रीका और अब यूक्रेन के कारण रूस और बेलारूस पर ओलम्पिक में लगी पाबंदी की मिसाल भी दी। लेकिन वह भूलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कदम सारी दुनिया ने इकट्ठा उठाया था। रूस और बेलारूस के खिलाफ सारा पश्चिमी ब्लाक इकट्ठा था।

हमारे साथ कौन है? पहलगाम को लेकर किसी भी देश ने खुलेआम पाकिस्तान की निन्दा नहीं की। गुड फ्रैंड डानल्ड ट्रम्प ने तो असीम मुनीर को लंच पर इन्वाइट कर लिया। अब भारत सरकार ने यहां हो रहे एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को खेलने की इजाज़त दे दी है पर इस कदम पर किसी भी टीवी चैनल पर गर्मागर्म बहस नहीं देखी गई, जैसे दिलजीत दोसांझ पर देखी गई थी।

यहां सरकार अपने ही विरोधाभास में फंसी है, अगर उनकी हॉकी टीम आ सकती है तो क्रिकेट की टीम क्यों नहीं? पहलगाम पर हमले का ज़बरदस्त जवाब दिया गया और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए याचना करनी पड़ी। वह हमारी पक्की नीति होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान कोई ऐसी शरारत करेगा तो हम ठोक देंगे। खेलों या फ़िल्मों के बारे भी स्पष्ट नीति होनी चाहिए। देश में बहुत उतेजना है जिसे कम करने की ज़रूरत है। उग्रवाद के टाइगर से उतरना बहुत मुश्किल होता है। जगह-जगह कोई देश भक्ति के, कोई भाषा के, तो कोई धर्म के ठेकेदार उग रहे हैं। मुम्बई में एक दुकानदार को थप्पड़ मारे गए, क्योंकि उत्तर भारत से गए इस व्यक्ति को मराठी नहीं आती। राज ठाकरे ने तो खुलेआम घोषणा की है कि उन की पार्टी उन नागरिकों को थप्पड़ मारेगी जो मराठी में नहीं बोलते। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का कहना है कि वह कार्यवाही करेंगे पर तीन हिस्सों में बंटी उस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं। ज़रूरत तो राज ठाकरे जैसों के खिलाफ कार्यवाही करने की है। अनावश्यक मराठी बनाम हिन्दी का मसला खड़ा किया जा रहा है। ऐसे तत्व वास्तव में देश विरोधी है और देश को बांट रहे हैं। पंजाब में सोशल मीडिया में सक्रिय कंचन कुमारी जिसने कमल कौर भाभी का नाम लिया हुआ था, की एक निहंग ने हत्या कर दी। शिकायत थी कि सोशल मीडिया पर अश्लील और अनैतिक चीजें डालने वाली इस महिला ने अपने नाम में 'कौर' डाल कर सिख मर्यादा का अपमान किया है। हो सकता है कि शिकायत सही हो, पर हत्या करना ? क़ानून को हमारे लोग बार-बार हाथ में क्यों लेने लगे है?

सरकारें भी कमजोर पाई जाती हैं। किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती। वोट के चक्कर में क़ानून का पालन करवाने से घबराती हैं। आर्टिस्ट या खिलाड़ी आसान टार्गेट है। यह दुख की बात है कि आहत होना और क़ानून हाथ में लेना अब हमारी राजनीति का हिस्सा बन गया है। हवा में नफ़रत घोल दी गई है। हम सोच में पीछे की तरफ़ जा रहे हैं। सरकार खुद उलझी लगती है जो पाकिस्तानी सेलेब्रिटीज़ के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे फ्लिप फ्लाप से पता चलता है। हमें समझना चाहिए कि हम कोई मामूली देश नहीं है। प्राचीन सभ्यता है, सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही अर्थ व्यवस्था है। पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है। हम उन्हें आसानी से सम्भाल सकते हैं। पर हमें आंतरिक तौर पर मजबूत होना है। असुरक्षा की भावना छोड़नी चाहिए। हमारा राष्ट्रवाद इतना कमजोर क्यों हो गया कि एक फ़िल्म जो यहां प्रदर्शित नहीं हो रही, को ले कर हम उत्तेजित हो रहे हैं? यह जनून का दौर कब रुकेगा?

सम्पादकीय...

टकराव के लिए जिम्मेवार कौन?

इतिहास में पहली बार सिखों के दो तख़्तों में टकराव देखने को मिल रहा है जिसे समाप्त करना अति आवश्यक है अन्यथा आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। युवा वर्ग इस सबके चलते ही आज सिखी से दूर होता चला जा रहा है मगर अफसोस कि इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। सिख समाज में जत्थेदारों का विशेष तौर पर दायित्व बनता है कि वह कौम के भीतर आए विवाद को समाप्त करके सभी सिखों को एकजुट होकर एक निशान साहिब के भीतर लाएं मगर आज तो जत्थेदार स्वयं विवाद के घेरे में आ चुके हैं अब इनमें एकजुटता कैसे और कौन लेकर आएगा यह अपने आप में प्रश्न बन गया है। असल में विवाद तब खड़ा हुआ जब श्री अकाल तख़्त साहिब से ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के द्वारा तख़्त पटना साहिब से तनखैया और पंथ से निष्कासित पूर्व जत्थेदार रणजीत सिंह गौहर को माफ करते हुए उन्हें पहले की भांति सेवाएं निभाने हेतु आदेश जारी कर दिया इतना ही इसके साथ ही तख़्त पटना साहिब के मौजूदा जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी बलदेव सिंह और ज्ञानी गुरदयाल की सेवाओं पर रोक लगा दी गई। इस पर तख़्त पटना साहिब के जत्थेदार सहित पांच प्यारे साहिबान के द्वारा ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज और ज्ञानी टेक सिंह को तनखैया करार देते हुए इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड के रूप में मानते हुए सुखबीर सिंह बादल को पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। हालांकि चाहिए तो यह था कि सुखबीर सिंह बादल पेश होकर अपना पक्ष रखते और वह शायद चाहते भी थे मगर उनके कुछ सलाहकार ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें ऐसा करने से रोका जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। 40 दिनों बाद भी जब सुखबीर बादल पेश नहीं हुए तो तख़्त पटना साहिब से उन्हें तनखैया कर दिया गया। जिसके बाद मानो पंजाब की राजनीति में भूचाल सा आ गया। सुखबीर के खिलाफ आदेश आते ही ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज तुरन्त हरकत में आए और अपने आका को बचाने के लिए उन्होंने तख़्त पटना साहिब के दो सदस्यों हरपाल सिंह जौहल और डा. गुरमीत सिंह सहित ज्ञानी गुरदयाल सिंह को भी तनखैया कर दिया। इस पर संसार भर से सिख बुद्धिजीवियों द्वारा चिन्तन किया जा रहा है और उनका मानना है कि सभी तख़्त अपने आप में सम्मानित हैं इसलिए सभी जत्थेदारों को चाहिए कि बड़े छोटे की बात ना करते हुए बिना वजह पंथ में उपजे मसले का समाधान निकालें। जो लोग स्वयं श्री अकाल तख़्त साहिब के आदेशों को दरकिनार करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हैं आज वही अकाल तख़्त की महानता की दुहाई दे रहे हैं इसलिए जत्थेदार साहिबान को चाहिए अपना नैतिक फर्ज समझते हुए राजनीतिक लोगों की गिरफ्त से बाहर आकर कौम हित में एकजुटता लाने की ओर अग्रसर हों और जल्द से जल्द इसका स्थाई हल निकाला जाए किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए पूरी कौम को दाव पर लगाना किसी भी सूरत में सही नहीं है। इतिहास गवाह है कि सिख गुरु साहिबान से लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर जैसे अनेक सिख योद्धा हुए जिनका इतिहास अगर बच्चे पढ़ लें तो वह सिखों के प्रति हीन भावना रख ही नहीं सकते। इतना ही नहीं अगर देशवासियों ने इतिहास पढ़ा होता तो 1984 में सिखों का कत्लेआम भी नहीं होना था और सिखों को खालिस्तानी या आतंकी कहकर भी नहीं पुकारा जाता। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहल पर अब छात्र मुगल राज्य और समाज पर विशेष रूप से तथा सामान्य रूप से भारतीय इतिहास पर उभरते इतिहास लेखन में विद्यमान अंतराल को समझ सकेंगे। कोर्स में यूनिट एक के तहत विद्यार्थियों को सिख धर्म का विकास, मुगल राज्य और समाज, पंजाब सिख धर्म में शहादत और शहादत की अवधारणा, सिख गुरुओं के अधीन सिख, गुरु नानक देव जी से गुरु रामदास जी तक सिख धर्म का ऐतिहासिक संदर्भ पढ़ाया जाएगा। यूनिट दो में शहादत की गाथा के तहत आधिपत्य मुगल राज्य और दमन, गुरु अर्जन देव जी, जीवन और शहादत, राज्य की नीतियों पर प्रतिक्रियाएं, गुरु हरगोबिंद जी से गुरु हरकृष्ण जी तक, गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शहादत, भाई मति दास, भाई सती दास, भाई दयाला के संदर्भ पढ़ाए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा इतिहास में सिख शहादतों और बहादुरी पर अंडरग्रेजुएट कोर्स शुरू करने को सिख समाज के लोग मोदी सरकार का सराहनीय कदम बताते हुए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते दिख रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिन्दर सिंह सिरसा मानते हैं कि इससे ही सरकारों की सोच का पता चलता है एक ओर आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों पर जुल्म करने वाले अत्याचारियों का इतिहास स्कूलों कालेजों में बच्चों को पढ़ाया मगर अत्याचार की उस आग को ठण्डा कर देश और धर्म की रक्षा वाले गुरु साहिबान और सिख योद्धाओं के इतिहास से वंचित रखा। तख़्त पटना साहिब कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो सहित अन्य सिख नेता भी सरकार के इस कदम की प्रशंसा करते दिख रहे हैं। कांवड़ियों के स्वागत में सिख समाज – सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्त कांवड़िए दिल्ली में दस्तक देने लगते हैं जो हरिद्वार से पैदल गंगाजल लेकर आते हैं और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने के पश्चात् ही अपने घरों में प्रवेश करते हैं। वैसे तो यह यात्रा पिछले कई सालों से चल रही है मगर मदन लाल खुराना की दिल्ली में सरकार आने के बाद से कांवड़ियों की गिनती में काफी इजाफा देखने को मिला। इस बार भी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा कांवड़ियों के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई है वहीं दिल्ली का सिख समाज भी इस बार कांवड़ियों के स्वागत के लिए कमर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जंगपुरा से विधायक तरविन्दर सिंह मारवाह जो कि केन्द्रीय गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष भी हैं उन्होंने ऐलान किया है कि सिख समाज कांवड़ियों के लिए लंगर और उनके रहने का प्रबन्ध गुरुद्वारों की सराओं में करेगा और साथ ही उन्होंने कांवड़ियों के रुट पर मीट और शराब की दुकानें बंद रखने की अपील भी की है।

बिहार में महिला आरक्षण

बिहार में आगामी नवम्बर-दिसम्बर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसे देखते हुए सत्ता और विपक्ष के दल अपनी-अपनी राजनैतिक चौसर बिछाने लगे हैं। ताजा फैसले में राज्य की भाजपा-जद(यू) नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 35 प्रतिशत आरक्षण को राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए आवश्यक करार दिया है। इससे पहले अन्य राज्यों की महिलाओं के लिए भी नौकरियों के द्वार खुले हुए थे। मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार महिला वर्ग में लोकप्रिय समझे जाते हैं। इसकी कई वजहें समझी जाती हैं। पहली तो यह कि उन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबन्दी करके घरेलू महिलाओं को राहत देने की कोशिश की थी। मुख्यमन्त्री का यह फैसला राज्य की महिलाओं ने बहुत सराहा था। इससे उनका पारिवारिक जीवन सुगम होने की संभावनाएं बढ़ी थीं। शराबबन्दी से गरीब तबके की महिलाओं में खुशी की लहर थी मगर दूसरा पहलू यह भी है कि इससे राज्य में अवैध तरीके से शराब तस्करी भी बढ़ी और राज्य में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ। नीतीश सरकार ने इस समस्या का हल पुलिस प्रशासन की मार्फत ढूंढने की कोशिश की जिसमें उसे आंशिक सफलता ही मिल पाई। यह भी सच है कि अवैध शराब की राज्य में तस्करी अब भी हो रही है और प्रशासन इसे पूरी तरह बन्द करने में सफल नहीं हो सका है। किसी भी समाज में ऐसी बुराई को जड़ से समाप्त करना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। फिर भी राज्य की महिलाओं ने मुख्यमन्त्री की शराबबन्दी की घोषणा का खुले दिल से स्वागत किया था। जहां तक महिलाओं के सरकारी नौकरियों में आरक्षण का सवाल है तो मुख्यमन्त्री ने यह फैसला 2016 में किया था। उस समय नीतीश बाबू जद(यू)-कांग्रेस व लालू जी की पार्टी राजद के महागठबन्धन की सरकार के मुखिया थे। इससे पहले 2015 को हुए राज्य विधानसभा चुनावों में इस गठबंधन को भाजपा के मुकाबले भारी सफलता मिली थी। इन चुनावों में राज्य की महिलाओं ने नीतीश बाबू का साथ दिया था। तभी से महिला वोट बैंक नीतीश बाबू का समझा जाता है। पिछले 20 साल से 2005 के बाद से नीतीश बाबू ही राज्य के मुख्यमन्त्री चले आ रहे हैं हालांकि राज्य में सत्तारूढ़ सरकार के गठबन्धन अदलते-बदलते रहते हैं। नीतीश बाबू कभी भाजपा के साथ मिलकर सत्ता में रहते हैं तो कभी कांग्रेस व लालू जी की पार्टी के साथ। अतः पिछले 20 सालों में बिहार सरकार ने जो भी फैसले जनहित में किये हैं उन सभी का श्रेय नीतीश बाबू को दिया जा सकता है। 2022 में उन्होंने बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराया था। उस समय नीतीश बाबू लालू जी की पार्टी के सहयोग से मुख्यमन्त्री बने हुए थे। इस सर्वेक्षण का श्रेय हालांकि लालू जी की पार्टी ने लेने का प्रयास किया मगर नीतीश बाबू ने स्पष्ट कर दिया कि इस फैसले में उनकी भागीदारी को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके पास राज्य के अति पिछड़े वर्ग का व्यापक समर्थन है। इस जातिगत सर्वेक्षण में साफ हुआ था कि बिहार में 36 प्रतिशत लोग अति पिछड़े वर्ग के हैं। जातिगत सर्वेक्षण के बाद नीतीश सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों की मदद के लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाये और अति गरीब परिवारों को दो लाख रुपये की मदद देने का फैसला भी किया। इस प्रकार नीतीश बाबू इस वर्ग की सहानुभूति बटोरने में पुनः सफल रहे। जहां तक विपक्ष का सवाल है तो वह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराये जाने के खिलाफ व्यापक अभियान चलाये हुए है और इस सन्दर्भ में उसने बुधवार को बिहार बन्द का आयोजन भी किया गया। इस बन्द के सफल होने की खबरें भी आ रही हैं जिससे इस चुनावी राज्य में जनता बनाम चुनाव आयोग की स्थिति पैदा होती जा रही है लेकिन नीतीश बाबू इस विवाद से तटस्थ बने हुए हैं और वह मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं। इससे पता चलता है कि मुख्यमन्त्री इस घटना के राजनीतिक हानि-लाभ के समीकरणों को तोल रहे हैं और सही समय पर अपनी बात कहने के इन्तजार में हैं लेकिन इस विवाद से लोगों खासकर महिलाओं का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरियों में स्थायी निवास वाली महिलाओं का मुद्दा गरमा दिया है। जाहिर तौर पर इससे नीतीश बाबू का महिला वोट बैंक सशक्त होगा। अभी तक यह व्यवस्था थी कि 35 प्रतिशत महिला आरक्षण में किसी भी राज्य की महिलाएं बिहार में नौकरी पा सकती थीं। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की नौकरियों में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी अच्छी-खासी संख्या में नौकरियां मिली थीं। अब ये सब नौकरियां केवल बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जायेंगी। इससे राज्य की राजनीति में जिस प्रकार जातिवाद का बोलबाला है वह भी कम होगा क्योंकि आरक्षण में हर जाति की महिला पात्र मानी जायेगी। इससे भाजपा को चुनावी मैदान में उतरने में मदद मिलेगी क्योंकि यह पार्टी मूल रूप से अगड़े समाज की पार्टी समझी जाती है। जद(यू) के साथ मिलकर ही भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े थे जिसमें उसे शानदार सफलता मिली थी। अतः विधानसभा चुनावों की चौसर में सत्ता व विपक्ष अपनी-अपनी गोटियां बहुत सावधानी के साथ बिछाते नजर आ रहे हैं।

मोदी सरकार की 11 साल की स्वास्थ्य सुधार यात्रा

स्वस्थ भारत कभी बस एक स्लोगन हुआ करता था, लेकिन पिछले ग्यारह सालों में यह एक सच्चाई बन गया, जिसे आंकड़ों के साथ परखा जा सकता है। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला, तब भारत का स्वास्थ्य बजट मात्र 33,278 करोड़ था। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा काफी बिखरी हुई थी और जब भी किसी के घर में बीमारी आती, लाखों लोग पुनः निर्धनता में चले जाते, लेकिन अब 2025-26 के बजट में यह खर्च लगभग तीन गुना बढ़कर 95,958 करोड़ हो गया है। यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य बदलाव है, जिसने स्वास्थ्य सेवा का प्रारूप हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस बदलाव की सबसे बड़ी बुनियाद है आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जिसने आज 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास एक ऐसा कार्ड मुहैया कराया, जिससे उन्हें हर साल अपने परिवार के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। यह इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में बड़े और गंभीर रोगों के लिए होता है। पिछले अक्तूबर में इस योजना में बड़ा परिवर्तन करते हुए 70 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए छूट दी गई, चाहे वो अमीर हों या गरीब। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। बीमा तो सिर्फ आधी तस्वीर है। इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा जन औषधि केंद्रों में दिखता है। 2014 के मात्र 80 दुकानों के छोटे नेटवर्क से बढ़कर आज ऐसे केंद्रों की संख्या 16,000 से ज्यादा है। इन दुकानों पर 2,000 से भी ज्यादा सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं, जो ब्रांडेड दवाओं से 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं। इस सुधार की वजह से भारतीय परिवारों ने अब तक अनुमानित तौर पर 28,000 करोड़ बचाए हैं। कोविड-19 महामारी, जो सौ साल में मानवता पर आई सबसे बड़ी आपदा मानी गई, उससे मुकाबले में भी हमारा दृढ़ निश्चय साफ नजर आया। जब यह महामारी आई, तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत में हालात बिगड़ जाएंगे, लेकिन भारत ने कोविन पोर्टल से जवाब दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा और पारदर्शी वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म था, जिसे वैक्सीन आने के बाद शीघ्र ही लॉन्च कर दिया गया था। मार्च 2025 तक भारत ने 220.6 करोड़ टीके लगा दिए, और ये संभव हुआ देश में ही बने कोविशील्ड, कोवैक्सिन और दूसरे मेड-इन-इंडिया टीकों की वजह से। अस्पतालों और दवाओं में आमूलचूल सुधार के साथ-साथ चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाना भी जरूरी था। इसलिए सरकार ने अस्पताल बनाने के साथ-साथ मेडिकल शिक्षा पर भी जोर दिया। मेडिकल कॉलेज 404 से बढ़कर 780 हो गए, एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई, एमबीबीएस की सीटें दोगुनी होकर 1.18 लाख हो गईं और पीजी यानी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीटें 31,000 से बढ़कर 73,000 से ज्यादा हो गईं। अब हमारे पास डॉक्टरों का अनुपात 1 डॉक्टर प्रति 834 लोग है साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना ने डॉक्टरों की शिक्षा और प्रैक्टिस में पारदर्शिता और गुणवत्ता में जरूरी बदलाव किया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार

चुनाव आयोग से कहा- आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र मानें

नई दिल्ली।

बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) मामले पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग को तीन दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार करने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं में लोकतंत्र से जुड़ा अहम सवाल उठाया गया है, जो मतदान के अधिकार से जुड़ा है. कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दे रहे हैं. इसे संविधान और कानून के प्रावधानों के खिलाफ बता रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 का भी हवाला दिया है. चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि 2003 में भी इंटेंसिव रिवीजन हुआ था. अब भी सही तरीके से इसे चलाया जा रहा है. याचिकाकर्ता कहते हैं कि विधानसभा चुनाव नवंबर में है. अधिसूचना उससे पहले जारी होगी. हमारा मानना है कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. हम एसआईआर पर रोक नहीं लगा रहे हैं. जज ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी और उससे पहले सभी पक्ष जवाब दाखिल करें. सुनवाई के दौरान जज ने कहा, आयोग के वकील ने कहा है कि वह सिर्फ 11 दस्तावेज तक सीमित नहीं है. हमारा सुझाव है कि चुनाव आयोग 3 दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को स्वीकार करने पर भी विचार करें. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, नागरिकता केंद्र सरकार तय करती है. यहां एक बूथ लेवल ऑफिसर को यह शक्ति दे दी गई है. केंद्र सरकार तय करेगी कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं. चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता. इस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा, हम सिर्फ मतदाता की पुष्टि करते हैं. अलग-अलग दस्तावेज का अलग महत्व होता है. हमने 11 दस्तावेज को मतदाता की पुष्टि के लिए मान्यता दी है.

डूब गई राजधानी... पानी में तैर रहे वाहन, गुरुग्राम में कई फीट नीचे धंस गई सड़क

नई दिल्ली। मानसून की पहली तेज वर्षा ने सड़कों पर जलभराव रोकने के इंतजामों की पोल खोल दी। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-70 स्थित एसपीआर रोड कई फीट नीचे धंस गई। सड़क धंसने से एक ट्रक भी गिर गया। बताया गया कि इस ट्रक में बीयर भरी हुई है। वहीं, कई जगहों पर जलभराव व जाम की स्थिति होने से गुरुवार सुबह भी लोगों को ऑफिस पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बता दें कि बुधवार शाम से शुरू हुई वर्षा देर रात तक जारी रही। कई सड़कों पर जलभराव हुआ और एनसीआर में महाजाम की स्थिति बन गई। दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में लोग कई किलोमीटर के लंबे जाम में घंटों फंसे रहे। वाहनों के बीच रास्ते में बंद होने से कई लोगों पर दोहरी मार पड़ी। हालत ऐसी थी कि शाम को कार्यालयों से निकले कई लोग मध्यरात्रि के बाद घर पहुंचे। दिल्ली में 150 से अधिक स्थानों पर जलभराव और 200 से अधिक स्थानों पर जाम लगा। वहीं, सरिता विहार अंडरपास में जलभराव के बीच जगुआर और जसोला में एक अन्य कार फंस गई। जलभराव से गुजरने में कई बसें जहां-तहां फंस गईं और इन बसों में बैठी सवारियों को वैकल्पिक व्यवस्था कर अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। कुल मिलाकर सड़कों पर जगह-जगह जलभराव ने दिल्ली सरकार के मानसून को लेकर तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। बताया गया कि देर रात दो बजे तक कहीं से कोई जनहानि की सूचना नहीं थी।

दो घंटे एक ही स्थान पर खड़ी रहीं एंबुलेंस

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर खेड़कीदौला से लेकर रजोकरी बार्डर तक 24 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया और घंटों तक वाहनों के पहिये थम गए। बताया गया कि जाम ऐसा था कि सैकड़ों वाहनों के साथ कई एंबुलेंस भी एक से दो घंटे तक एक ही स्थान पर खड़े रहे। बढ़ते-बढ़ते जाम दिल्ली तक पहुंच गया। गाजियाबाद का भी बुरा हाल रहा। राजनगर एक्सटेंशन में लगभग 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर भी काफी संख्या में वाहनों की कतारें लगी रहीं।

हर बार वर्षा में मिंटो ब्रिज अंडरपास में जलभराव होता था, लेकिन इस बार वहां पानी की निकासी की व्यवस्था होने के कारण लोगों को राहत मिली। कई लोगों ने वहां से फेसबुक लाइव भी किया। पटपड़गंज के विधायक रवि नेगी पिछले साल पार्षद थे। तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उस समय जलभराव के कारण एनएच-9 पर विनोद नगर के पास वह नाव चलाते दिखते थे। इस बार वह विधायक हैं तो उसी स्थान पर रात करीब 11:00 बजे दो ट्रैक्टर की मदद से पानी की निकासी कराते नजर आए।

कांग्रेस का पीएम मोदी पर तीखा वार - वे चाहें तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता और मणिपुर का दौरा कर सकते हैं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की आधिकारिक यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि अब जब प्रधानमंत्री देश में वापस आ गए हैं, तो उन्हें देश के अंदरूनी मुद्दों पर ध्यान देने का समय निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्राजील में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसके अलावा घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जैसे पांच देशों का दौरा किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कटाक्ष करते हुए लिखा, भारत अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, जो शायद अगली विदेश यात्रा से पहले तीन हफ्तों के लिए देश में रहेंगे।

मणिपुर, जीएसटी और संसद सत्र- कांग्रेस की मांगें

रमेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब जब प्रधानमंत्री देश में हैं, तो शायद उन्हें मणिपुर जाने का समय मिल जाए, जहां लोग दो साल से भी ज्यादा समय से उनका इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि मणिपुर पिछले दो सालों से जातीय हिंसा की चपेट में है।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की है

जीएसटी में सुधार- रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहें तो जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में बड़े सुधार पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिससे आम लोगों की खरीद शक्ति बढ़ सके और बड़ी कंपनियों के अलावा बाकी निजी कंपनियां भी निवेश के लिए प्रेरित हों।

सर्वदलीय बैठक- उन्होंने सुझाव दिया कि बदलाव के तौर पर प्रधानमंत्री 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के लिए एजेंडा तय करने के उद्देश्य से एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं।

पहलगाम और गृह राज्य के मुद्दे - कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पहलगाम में आतंकवादियों को अब तक न्याय के कटघरे में क्यों नहीं लाया गया, इसकी समीक्षा करने और अपने गृह राज्य (गुजरात) में लगातार गिरते-ढहते बुनियादी ढांचे पर भी विचार करने के लिए समय निकालने को कहा।

कांवड़ यात्रा मार्ग में ढाबों पर फूड सेफ्टी स्टिकर्स अनिवार्य, कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली।

11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने तीर्थयात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता अभियान को तेज कर दिया है। इसके तहत सभी भोजनालयों के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े क्यूआर-कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य इस वर्ष यात्रा पर आने वाले अनुमानित चार करोड़ तीर्थयात्रियों के लिए स्वच्छता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की विशेष सचिव एवं अपर आयुक्त रेखा एस चौहान ने बताया कि राज्य भर के सभी कांवड़ मार्गों पर हमने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जहां हम सभी रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों पर सेफ्टी ऐप कनेक्ट स्टिकर चिपका रहे हैं। हमने रेस्टोरेंट मालिकों को बेची जा रही सभी वस्तुओं की रेट लिस्ट लगाने का भी निर्देश दिया है। सभी मार्गों पर खाने-पीने की चीजों और स्वच्छता की भी जाँच की जा रही है। ढाबों, रेस्टोरेंट और भंडारा आयोजकों को भोजन तैयार करते समय गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। इमरान मसूद ने पूछा कि क्या वे रोजगार के अवसरों के लिए भी क्यूआर कोड लगाएंगे? उन्होंने कहा कि त्योहारों पर क्यूआर कोड लगाकर वे नफरत फैला रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं। वे देश को कहां ले जाना चाहते हैं? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन वे इस पर बात नहीं करना चाहते। हालांकि इस साल नेमप्लेट या धार्मिक पहचान के बारे में कोई नया निर्देश नहीं आया है, लेकिन मालिक के नाम और पंजीकरण वाले डिजिटल स्टिकर ने जुलाई 2024 की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब यूपी पुलिस ने 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों को अपना नाम और फोन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का एक विवादास्पद आदेश जारी किया था। यह आदेश, जिसे बाद में सरकार ने 9 जुलाई, 2024 को पूरे राज्य में लागू कर दिया, कई लोगों ने इसे हिंदू नामों से संचालित मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकानों की पहचान करने के प्रयास के रूप में देखा। धार्मिक पहचान की घटनाओं की रिपोर्ट के बाद इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें एक चौंकाने वाला मामला भी शामिल था जहाँ एक स्वयंभू धार्मिक नेता की टीम ने एक रेस्टोरेंट कर्मचारी को अपना धर्म साबित करने के लिए आंशिक रूप से कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया।

गुजरात का महिसागर पुल हादसा- नदी से 15 शव मिले, 4 लोग अब भी लापता

अहमदाबाद।

गुजरात में वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला पुल टूटने के बाद महिसागर नदी से 15 शव निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ को गुरुवार सुबह 2 शव मिले, जबकि 13 बुधवार को ही बरामद हो चुके थे। हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है। अभी भी 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश जारी है। महिसागर नदी पर बना ब्रिज बुधवार सुबह टूट गया था। चलते ट्रैफिक के बीच पुल टूट जाने से दो ट्रक, दो कार और एक रिक्शा नदी में गिर गया था। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया था। 45 साल पुराना यह ब्रिज दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। इसके टूटने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और वलसाड से सौराष्ट्र पहुंचना मुश्किल हो गया है। अब इसके लिए अहमदाबाद होकर जाना होगा।

नगर निकाय चुनावों में नहीं होगा कोई भी इंडिया गठबंधन : संजय राउत

मुंबई।

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनावों में कोई भी इंडिया गठबंधन नहीं होगा। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा राज्य में हिंदी थोपने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए अपने मतभेदों को भुलाने के बाद, अब इन दोनों दलों पर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनावी गठबंधन बनाने का जनता का दबाव है, जो बिहार चुनावों के आसपास होने की उम्मीद है। संजय राउत ने आगे दावा किया कि मैंने यह नहीं कहा कि शिवसेना और मनसे मिलकर (स्थानीय निकाय) चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि जनता की ओर से शिवसेना और मनसे पर स्थानीय निकाय चुनाव साथ लड़ने का दबाव और मांग है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों का मानना है कि अगर मराठी मानुस के अधिकारों की रक्षा करनी है, तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ आना होगा....राज ठाकरे का काम करने का तरीका अलग है। संजय राउत के बयान पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मैं संजय राउत पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने कई बार कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को विश्वास में लेकर लड़े जाते हैं। इसलिए इन चुनावों को इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या एमएनएस गठबंधन में शामिल होने पर एमवीए को मजबूत करेगी, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, हमने हमेशा कहा है कि हमारा हाई कमान इस पर फैसला करेगा। अगर हमारे गठबंधन के बाहर कोई भी गठबंधन में शामिल हो रहा है, तो निर्णय हमारे हाई कमान द्वारा किया जाएगा।

भाजपा नेतृत्व और सरकार उदासीनता की सारी हदें पार कर चुके हैं : खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरात के वडोदरा में एक पुल ढहने की घटना का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सिर्फ भाषण और विज्ञापनबाजी में व्यस्त भाजपा नेतृत्व और सरकार उदासीनता की सारी हदें पार कर चुके हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि यह नेतृत्व संकट, चौतरफा भ्रष्टाचार और सरकार चलाने की क्षमता में कमी का नतीजा है। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, देश में आए दिन दुर्घटनाएँ आम बात हो गई हैं। कभी रेल दुर्घटना, कहीं उद्घाटन के साथ ही पुल में दरार आना। अभी विमान दुर्घटना के हादसे से देश उबर नहीं पाया है कि कल गुजरात से पुल ढहने की खबर आ गई। 13 मासूम जानें चली गईं। उन्होंने पीड़ितों के परिजन के प्रति संवेदना प्रकट की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, खबरों के अनुसार तीन साल पहले ही पुल हिलने से खतरनाक स्थिति की बात कही गई थी। फिर भी कुछ नहीं किया गया। 2021 से यह गुजरात में पुल गिरने की सातवीं घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में शासन के नाम पर केवल भाषण और विज्ञापनबाजी में व्यस्त भाजपा नेतृत्व और सरकार उदासीनता की सारी हदें पार कर चुके हैं। खरगे ने दावा किया कि यह नेतृत्व संकट, चौतरफा भ्रष्टाचार और सरकार चलाने की क्षमता में कमी, और अक्षमता का नतीजा है। उन्होंने कहा, उम्मीद है देश की जनता इसे देख रही है और समय आने पर इसका माकूल जवाब देगी।

सत्ता में कोई साझेदारी नहीं, मैं ही सीएम रहूंगा, नेतृत्व विवाद के बीच बोले सीएम सिद्धारमैया

बंगलूरू। कर्नाटक नेतृत्व को लेकर ऊहापोह की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि वह पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और उन्होंने दावा किया कि उनके और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता में साझेदारी का कोई समझौता नहीं हुआ है। गौरतलब है कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, दोनों ही नेता दिल्ली में हैं, जहां वे राहुल गांधी समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के दिल्ली में होने के बाद कर्नाटक में फिर से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरू हो गई। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने स्वीकार किया कि शिवकुमार भी मुख्यमंत्री पद चाहते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन शिवकुमार ने खुद स्पष्ट किया है कि सीएम का पद फिलहाल खाली नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कभी यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्री को बदला जाना चाहिए। मैं पूरे कार्यकाल के लिए सीएम हूं। मैं 2028 के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी का नेतृत्व करूंगा। उन्होंने आगे कहा, हालांकि, मैं आलाकमान के आदेशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। शिवकुमार और मैं, दोनों ही आलाकमान के फैसलों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। फिलहाल, सत्ता-बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी सख्त, विजय देवरकोंडा व प्रकाश राज समेत 29 अभिनेताओं-यूट्यूबर्स पर केस

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। तेलंगाना में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज जैसे अभिनेताओं के अलावा कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व यूट्यूबर्स सहित दो दर्जन से अधिक लोगों भूमिका की पड़ताल के लिए धन शोधन का मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इन दुकानों पर अवैध सट्टेबाजी और जुए के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध धनराशि अर्जित करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने के लिए पांच राज्य पुलिस प्राथमिकियों का संज्ञान लिया है। ईडी मामले में देवरकोंडा, दग्गुबाती, मांचू लक्ष्मी, राज, निधि अग्रवाल, प्रणिता सुभाष, अनन्या नागल्ला, टीवी होस्ट श्रीमुखी के अलावा स्थानीय सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर्स सहित लगभग 29 हस्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इन हस्तियों पर सेलिब्रिटी या विज्ञापन शुल्क प्राप्त करने के बदले जंगली रम्मी, जीतविन, लोटस 365 आदि जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का समर्थन करने का संदेह है। सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ जाने-माने व्यक्तियों ने पहले कहा था कि उन्हें उनके द्वारा पेश किए गए ऐप्स और उत्पादों की सटीक कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं थी और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सट्टेबाजी जैसी किसी भी गलत गतिविधि या अवैध गतिविधि के लिए इन प्लेटफार्मों के साथ खुद को नहीं जोड़ा। ईडी द्वारा आने वाले दिनों में उनके बयान दर्ज किए जाने की उम्मीद है, साथ ही वह और अधिक एफआईआर एकत्र कर रहा है और उन अधिक शिकायतकर्ताओं की तलाश कर रहा है, जिन्हें इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों द्वारा ठगा गया था।

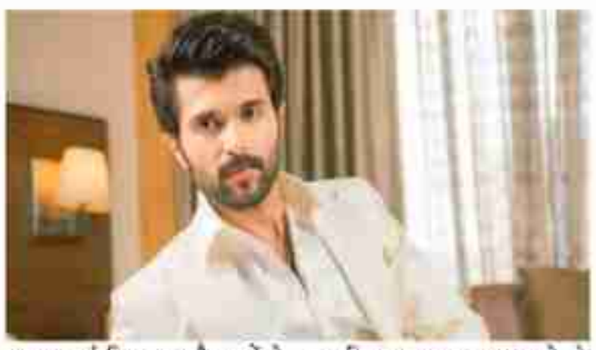

इन एप से होने वाली अपराध की आय की अनुमानित राशि और इन मशहूर हस्तियों की वास्तविक भूमिका का पता लगाने के लिए एक व्यापक जाँच चल रही है। सूत्रों ने बताया कि उनके बयान और बयान दर्ज होने के बाद ही उनके अपराध का फैसला किया जाएगा।

यमन में भारतीय नर्स निमिषा को बचाने की आखिरी कोशिश! सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ तैयार

नई दिल्ली। यमन में मौत की सजा पाई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की संभवतः आखिरी कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा प्रिया को बचाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी इस मामले की सुनवाई में शामिल होने को कहा है। निमिषा प्रिया को यमन में यमनी नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को मौत की सजा दी जा सकती है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले को 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कूटनीतिक तरीके से निमिषा को बचाने की कोशिश की जा सकती है। वकील ने कहा कि मृतक के परिवार को ब्लड मनी देकर निमिषा की सजा माफ कराई जा सकती है। निमिषा प्रिया (38 वर्षीय) केरल के पलक्कड़ जिले की निवासी है और उसे साल 2017 में यमन में अपने बिजनेस पार्टनर महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया है। निमिषा को महदी की हत्या के मामले में साल 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी। निमिषा की अंतिम याचिका को यमन की अदालत ने साल 2023 में ही खारिज कर दिया था। निमिषा को बचाने में जुटे एक संगठन से जुड़े लोगों ने दावा किया है कि निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। निमिषा को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि महदी के परिजन उसे माफ कर दें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निमिषा के परिजनों और समर्थकों ने 10 लाख डॉलर दियाह या ब्लड मनी की पेशकश की है, लेकिन निमिषा का बचना तभी मुमकिन है, जब महदी का परिवार इस रकम को स्वीकार करे और निमिषा को माफ कर दे। निमिषा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए यमन गई थी। कुछ समय बाद निमिषा ने यमन के नागरिक महदी के साथ मिलकर अपना क्लीनिक खोलने का फैसला किया। साल 2017 में महदी का शव मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निमिषा इस समय यमन की राजधानी सना की केंद्रीय जेल में बंद है। निमिषा पर आरोप है कि उसने महदी को बेहोशी की दवा की ज्यादा खुराक देकर मार डाला। हालांकि निमिषा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और यमन की कोर्ट में निमिषा के वकील ने तर्क दिए थे कि महदी ने उसे शारीरिक यातनाएं दीं, उनका सारा पैसा छीन लिया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उसे डराया-धमकाया। निमिषा के वकील ने कोर्ट से कहा था कि निमिषा सिर्फ बेहोशी की दवा देकर महदी से अपना पासपोर्ट वापस हासिल करना चाहती थी, लेकिन दुर्घटनावश दवा की मात्रा अधिक हो गई। जिससे महदी की मौत हो गई। जनवरी 2024 में यमन के हूती विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने भी निमिषा को फांसी देने की मंजूरी दे दी। निमिषा की मां साल 2024 से यमन में हैं और अपनी बेटी को बचाने की कोशिशों में लगी हुई हैं।

हरियाणा में बड़ा हादसा : छह लोगों पर गिरी दीवार, एक ही परिवार के तीन की मौत, तीन घायल

पलवल । हरियाणा के पलवल स्थित गांव सोफ्ता में बुधवार रात एक ही परिवार पर कहर टूट पड़ा। तेज बारिश के बीच पेट्रोल पंप की एक दीवार भरभराकर गिर गई और नीचे दबने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग समेत तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में पिता जगदीश के दामाद रवी (30), भतीजा पंकज (18) और बेटा राजबीर (20) शामिल हैं। रवी और पंकज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि राजबीर ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में आखिरी सांस ली। आरोप है कि गंभीर रूप से घायल हुए जगदीश के दो बेटे श्रीकांत (18), मनफूल (15) और एक अन्य प्रियांशु (18) को पहले फरीदाबाद के बीके अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बिना ही दिल्ली रेफर कर दिया गया। जगदीश ने बताया कि ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, जोकि एक पान मसाला कंपनी में नाइट ड्यूटी करते थे। बुधवार रात ये सभी रोज की तरह निकले, लेकिन बारिश की वजह से मुख्य रास्ते में पानी भर गया था। मजबूरी में पहली बार करीब नौ बजे पेट्रोल पंप के पास के रास्ते से निकलने लगे। इसी दौरान पेट्रोल पंप की दीवार अचानक गिर पड़ी। जगदीश ने बताया कि जमीन धंसी और दीवार सीधे बच्चों के ऊपर गिर गई। रवि मेरा दामाद था, पंकज मेरा

भतीजा और राजबीर मेरा जवान बेटा। वहीं श्रीकांत और मनफूल मेरे छोटे बेटे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जगदीश ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। बीके अस्पताल में न तो पट्टी की गई, न कोई दवा दी गई। सीधे रेफर कर दिया। दीवार के बारे में जगदीश ने बताया कि वह करीब नौ फीट ऊंची और सौ फीट लंबी थी, लेकिन उसमें न तो बीम था, न ही पिलर।

यह दीवार सिर्फ ईंटों से बनाई गई थी, पीछे बारिश का पानी भी जमा था, जिससे वह और कमजोर हो गई थी। जगदीश ने बताया कि मेरे परिवार के सभी लोग रोज एक ही रास्ते से फैक्ट्री जाते थे, लेकिन बुधवार को रास्ते में पानी भर गया था। मजबूरी में पेट्रोल पंप के पीछे की तरफ से गए। उस जगह से पहले कभी कोई नहीं गया था। पहली बार जो रास्ता चुना, वह जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। जगदीश ने बताया, हम घटनास्थल से घायलों को बीके अस्पताल लेकर पहुंचे। सोचा था यहां कुछ मदद मिलेगी। लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार में न कोई जांच की, न पट्टी की, न भर्ती किया। सीधे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। जगदीश के अनुसार, जिस दीवार के नीचे उनका परिवार दबा, उसमें कोई पिलर नहीं था, कोई बीम नहीं थी। बस ईंटों से जोड़कर दीवार खड़ी कर दी थी। पीछे बारिश का पानी इकट्ठा था, इस कारण जमीन धंस गयी जिससे दीवार पर दबाव बढ़ गया। यही वजह थी कि वो अचानक गिर गई। ऐसी लापरवाही की कीमत मैंने अपनों की जान देकर चुकाई है।

साल 2025 हमारे लिए आसान नहीं, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले- पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन हो रहा बहाल

श्रीनगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन बहाल होने को लेकर आशा का माहौल है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। यहां यात्रा और पर्यटन पर एक कार्यक्रम में अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकी हमले के बाद पर्यटन के ''पटरी पर लौटने के साथ जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत की उम्मीद है। अब्दुल्ला ने कहा, ''2025 हमारे लिए आसान साल नहीं है। इस साल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है - पहलगाम हमले से पहले और बाद में। हम सब देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन फिर से पटरी पर लौट रहा है। यह आशा का संदेश है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग जम्मू कश्मीर के साथ हैं और दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध ''विश्वास और स्नेह के संदर्भ में समय के साथ और भी मजबूत होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ''पश्चिम बंगाल राजनीतिक और आर्थिक, दोनों ही रूपों में जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है। जमीनी स्तर पर, एक नयी शुरुआत की उम्मीद का माहौल है। अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, ''पहलगाम की घटना के बाद मैं सभी की चिंता समझता हूं।

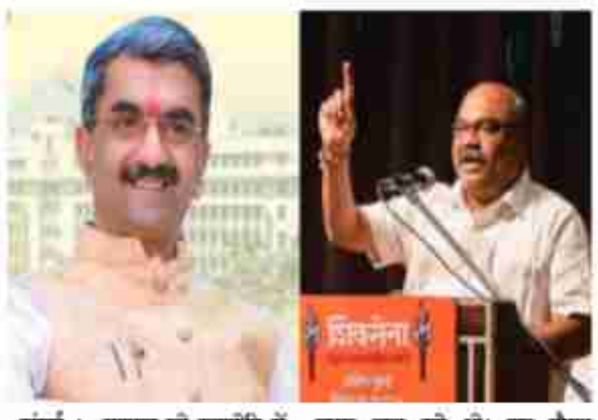

नई दिल्ली, (इंद्रजीत सिंह) मुंडका, अभिनंदन वाटिका पे संगठन सृजन अभियान, कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर पे अशोक सम्राट बुद्ध विहार प्रबंधक कमिटी द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर, पूर्व जिलाध्यक्ष साधुराम मित्तल, पूर्व प्रत्याशी निगम सुरेंद्र लकड़ा और युवा नेता ,तनुज कुमार को तथागत गौतम बुद्ध का चित्र भेंट करते, जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक बवाना सुरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज तथा संयोजक, विजय कुमार भारती तथा डाबर, इंद्रजीत सिंह व हिमांशु गौतम साथ में हिमांशु गौतम समारोह संपन्न हुआ आया - एस के गौड़

विधान परिषद में गद्दार शब्द को लेकर हंगामा, शिंदे गुट के मंत्री और उद्धव गुट के एमएलसी आमने-सामने

मुंबई । महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे और उद्धव गुट के बीच चल रही तनातनी अब विधान परिषद के अंदर भी दिखने लगी है। मुंबई में गुरुवार को राज्य विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता अनिल परब और राज्य के मंत्री शंभुराज देसाई के बीच तीखी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि परब ने देसाई को गद्दार कह दिया, जिस पर मंत्री ने भी उसी लहजे में जवाब दिया और दोनों आमने-सामने आ गए।यह विवाद तब शुरू हुआ जब विधान परिषद में मराठी भाषी लोगों को मुंबई और आसपास के इलाकों में कानूनी सुरक्षा के साथ आवास देने को लेकर बहस चल रही थी। इस दौरान बीजेपी की विधान परिषद सदस्य चित्रा वाघ ने सवाल किया कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार ने इस विषय पर कोई कानून बनाया था। जवाब में पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि उस सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था।

'गद्दार' शब्द से भड़के मंत्री, दिया खुला जवाब

शंभुराज देसाई ने खुद बताया कि उन्होंने अपने जवाब में उद्धव ठाकरे सरकार का उल्लेख किया था, जिसमें वे पहले मंत्री थे। इसी बात पर अनिल परब ने उन्हें 'गद्दार' कह दिया। देसाई ने भी उसी भाषा में पलटवार किया। मामला इतना बढ़ गया कि परब ने उन्हें सदन के बाहर निपटने की चेतावनी दी। इस पर देसाई ने कहा कि वह बाहर आमने-सामने होने को तैयार हैं।

उपसभापति ने रोकी कार्यवाही, केबिन में समझाइश

हंगामे को देखते हुए विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोर्हे ने सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने दोनों नेताओं को अपने केबिन में बुलाकर बातचीत की। देसाई ने बताया कि उपसभापति ने सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए 'गद्दार' जैसे शब्दों को कार्यवाही से हटाने का फैसला लिया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू की गई।

शिवसेना में फूट के बाद से लगातार जारी है तकरार

गौरतलब है कि जून 2022 में शिवसेना में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत हुई और पार्टी दो गुटों में बंट गई। तब से लेकर अब तक उद्धव ठाकरे गुट लगातार शिंदे गुट के नेताओं को 'गद्दार' कहकर निशाना बना रहा है। अब यह शब्दावली विधान परिषद जैसे संवैधानिक मंच तक पहुंच गई है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को मिली बड़ी राहत; खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव

स्ट्रासबर्ग । यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दक्षिणपंथी यूरोपीय सांसदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मतदान में खारिज हो गया। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र के दौरान 18 सांसदों द्वारा मतदान में भाग न लेने के कारण प्रस्ताव 360-175 मतों से खारिज हो गया। मतदान के दौरान उर्सुला उपस्थित नहीं थी। 2024 में उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय आयोग की दूसरी बार अध्यक्ष बनी थीं। अविश्वास प्रस्ताव में वॉन डेर लेयेन के खिलाफ कई आरोपों को शामिल किया गया था। इनमें कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन निर्माता फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ निजी तौर पर टेक्स्ट मैसेजिंग, यूरोपीय संघ के धन का दुरुपयोग और जर्मनी और रोमानिया में चुनावों में हस्तक्षेप शामिल था। इस दौरान, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले रोमानिया एमईपी घोरघे पिपेरेया ने कोविड के दौरान फाइजर की सीईओ अल्बर्ट बौर्ला के साथ चैट को लेकर वॉन डेर लेयेन की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की। पिपेरेया ने यूरोपीय आयोग पर रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगाया। वहीं, इससे पहले मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने खुद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से पहले अपना बचाव किया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि राजनीतिक विरोधी उनके और कोविड-19 महामारी को लेकर साजिश रच रहे हैं। लेयेन ने कहा था कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद कट्टर दक्षिणपंथी हैं। उनका मकसद संसद में यूरोप समर्थक राजनीतिक समूहों के बीच फूट डालना है। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में एक पूर्ण सत्र के दौरान उन्होंने कहा, हम कभी भी चरमपंथियों को इतिहास को फिर से लिखने नहीं दे सकते। साल 2021 में यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों ने यूरोपीय आयोग से कोविड टीकों को लेकर समझौतों का पूरा विवरण मांगा था, लेकिन आयोग केवल कुछ अनुबंधों और दस्तावेजों तक आंशिक पहुंच प्रदान करने के लिए सहमत हुआ, जिन्हें संशोधित संस्करणों में ऑनलाइन रखा गया था। इसने यह बताने से भी इनकार कर दिया कि उसने अरबों खुराकों के लिए कितना भुगतान किया, यह तर्क देते हुए कि गोपनीयता कारणों से अनुबंधों को संरक्षित किया गया था। इस पर यूरोपीय संघ की अदालत ने भी कहा था कि यूरोपीय आयोग ने महामारी के दौरान दवा कंपनियों के साथ किए गए कोविड-19 वैक्सीन खरीद समझौतों के बारे में जनता को पर्याप्त जानकारी नहीं दी।

भारत पोस्ट के पास दुनिया बदलने की ताकत, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- अब ग्लोबल लीडर बनना लक्ष्य

बेंगलुरू । केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने भारत पोस्ट की ताकत और उसके भविष्य को लेकर एक बड़ी बात कही है। बेंगलुरु में आयोजित 'ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन' में उन्होंने कहा कि भारत पोस्ट जैसा कोई दूसरा वितरण नेटवर्क पूरी दुनिया में नहीं है। उन्होंने डाक विभाग के कर्मचारियों से अपील की कि वे भारत पोस्ट को विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स संस्था बनाने की दिशा में काम करें। सिंधिया ने कहा कि आज भारत पोस्ट के पास पूरे देश में 1.64 लाख से ज्यादा सेवा केंद्र हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और भरूच से लेकर तवांग तक फैले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी गहरी और व्यापक पहुंच किसी और संस्था के पास नहीं है। यह नेटवर्क देश के हर कोने तक लोगों और सेवाओं को जोड़ता है, जो भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उन्होंने बताया कि डाकघर अब आधुनिक हो रहे हैं। हाथ में पकड़े जाने वाले डिजिटल उपकरण और 'दर्पण' जैसी तकनीकें डाक विभाग में आ चुकी हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ तकनीक से बदलाव नहीं होगा, जब तक कि कर्मचारियों का काम करने का तरीका नहीं बदलेगा। असली बदलाव कर्मचारियों की सोच और कार्यशैली में नयापन लाने से ही आएगा। सिंधिया ने डाक कर्मचारियों से कहा कि वे सिर्फ सरकारी सेवा को काम की तरह न लें, बल्कि इसे देश के निर्माण में योगदान के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक देश की रीढ़ हैं जो सबसे दूर-दराज इलाकों में भी सेवाएं पहुंचाते हैं। यही वजह है कि अगर ये बदलेंगे तो देश का डाक तंत्र एक नए युग में प्रवेश करेगा। संचार मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि आज भारत पोस्ट सिर्फ पत्र पहुंचाने तक सीमित नहीं है। अब यह बैंकिंग, बीमा, ई-कॉमर्स डिलीवरी और डिजिटल सेवाओं का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आने वाले समय में यह न सिर्फ ग्रामीण भारत की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। सिंधिया की यह बात स्पष्ट संकेत देती है कि भारत पोस्ट को एक नई पहचान देने की तैयारी तेज हो चुकी है।

यूक्रेन को लेकर अमेरिकी नीति में असमंजस के हालात, पेंटागन ने हथियारों की सप्लाई फिर शुरू की

वॉशिंगटन ।

यूक्रेन नीति को लेकर ट्रंप प्रशासन में असमंजस और समन्वय की कमी नजर आ रही है। दरअसल बीते दिनों खबर आई थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को कई हथियारों की आपूर्ति रोक दी है। अब खबर आई है कि ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। जो हथियार भेजे जा रहे हैं, उनमें 155 एमएम के गोला बारूद और गाइडेड रॉकेट शामिल हैं।

हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है कि हथियारों की आपूर्ति कब शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बीते हफ्ते यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोकने का निर्देश दिया था। दरअसल पेंटागन द्वारा हथियारों के स्टॉक की समीक्षा के लिए आपूर्ति रोकी गई थी। हालांकि इस फैसले पर व्हाइट हाउस ने हैरानी जताई है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन को भेजे जाने वाले

हथियारों पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई थी। हालांकि सुरक्षा रणनीति के तहत अमेरिकी सेना के हथियारों के स्टॉक की समीक्षा की गई थी। बीते हफ्ते पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यूक्रेन को किन हथियारों की आपूर्ति रोकी गई, उसकी वे जानकारी नहीं दे सकते और अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ही इस बारे में फैसला लेंगे। इससे साफ है कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के मुद्दे पर समन्वय की कमी है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी। पूर्व में जब हथियारों की सप्लाई रोकने की खबर सामने आई थी तो बताया गया कि पैट्रियट मिसाइलों, जीएमएलआरएस रॉकेट, हेलफायर मिसाइल, होवित्जर राउंड आदि की आपूर्ति रोकी गई। अब ये साफ नहीं है कि पैट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति फिर शुरू की गई है या नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका, यूक्रेन को रक्षात्मक हथियार पहुंचाना जारी रखेगा। हाल ही में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि हथियारों की आपूर्ति रोकने का आदेश किसने दिया। ट्रंप ने हथियारों की आपूर्ति पर रोक के लिए पेंटागन के अधिकारियों से निराशा जाहिर की। वहीं पेंटागन ने इस बात से इनकार किया है कि रक्षा मंत्री हेगसेथ ने राष्ट्रपति से सलाह लिए बिना कोई कार्रवाई की।

अमेरिका का यह कदम ऐसे समय सामने आया है, जब रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कही थी, लेकिन युद्धविराम समझौते पर सहमति नहीं बनने के बाद अब लग रहा है कि ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से खुश नहीं हैं और अमेरिका द्वारा हथियारों की आपूर्ति भी उसी ओर इशारा कर रही है।

जयपुर गोल्डन अस्पताल बना ठगी का अड्डा।

नई दिल्ली. (कार्यालय संवाददाता) को बताया सरकार से सस्ते में जमीन और ग्रांट लेकर बनाया गया जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाएं देने के नाम पर ठगी का अड्डा बनता जा रहा है ठग डॉक्टर की मदद से जोकि मरीज , गरीबों और देश की सेवा करने के नाम पर बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल करके आए हैं। जयपुर गोल्डन अस्पताल में में हो रही इस तरह ठगी का नमूना पिछले दिनों तब देखने को मिला जब एक, मरीज को इलाज करने के लिए आउटडोर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में अपनी पति को देखने के लिए ओ पी डी, डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने इलाज के नाम पर बड़े-बड़े टेस्ट लिखकर दिये और मरीज देखने के नाम पर एक तगड़ी रकम ऐंठ ली इस विषय में पेशेंट ने अपने अधिकार के तहत जब स्पष्टीकरण मांगा तो डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने उनसे मेरा कहा की डॉक्टरी मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस से मैं ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहती हूं इतना कहकर उन्होंने पेशेंट से अपशब्द बोलते हुए उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया इस विषय में मरीज ने तुरंत ही जयपुर गोल्डन की एम एस, डॉ सुनीता से संपर्क किया तो उन्होंने यह माना कि डॉक्टर गरिमा गुप्ता इस तरह की बदतमीजी करने के लिए मशहूर है और उनका इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अस्पताल को तगड़ी रकम कमीशन के रूप में कमा कर दे रही हैं, परेशान होकर मरीज ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है और न्याय की मांग करते हुए जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल और उसमें बैठने वाले डॉक्टर पर लगाम कसने की अपील की है उल्लेखनीय है कि इस तरह की एक घटना कुछ समय पहले भी जयपुर गोल्डन अस्पताल में घटी थी जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग में की गई तो जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से माफी मांग कर और संबंधित मरीज को अपना रुतबा दिखाकर शांत कर दिया गया था, शिकायत हो चुकी है अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई कितनी जल्दी और कितनी तत्परता से होती है।

शेख हसीना पर प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले में चलेगा मुकदमा, पुलिस प्रमुख ने कबूल किया गुनाह

ढाका । बांग्लादेश की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। सत्ता से बेदखल की जा चुकीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब एक गंभीर मामले में कानूनी घेरे में आ गई हैं। देश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में औपचारिक रूप से आरोपित किया है। यह मामला पिछले साल जुलाई-अगस्त में छात्र आंदोलनों के दमन से जुड़ा है, जब प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से अत्याचार किए गए थे। इस मामले में शेख हसीना के अलावा दो और अहम नाम भी शामिल हैं पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान और पूर्व पुलिस महानिदेशक अब्दुल्ला अल मामून। इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर छात्र आंदोलनों को दबाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया और निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार कराए। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने इन पर मानवता के खिलाफ संगठित अपराध के तहत मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार एकमात्र व्यक्ति पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून हैं। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अदालत से राज्य का गवाह बनने की इजाजत मांगी है। उनकी याचिका के बाद यह केस और भी अहम हो गया है, क्योंकि उनके बयान से शेख हसीना और अन्य पर आरोप तय करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को भारत आ गई थीं, जब उनकी सरकार को सत्ता से हटाया गया था। इस समय वे बांग्लादेश में मौजूद नहीं हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि उनकी गैरहाजिरी में भी मुकदमा चलाया जाएगा। यही बात पूर्व गृह मंत्री पर भी लागू होगी, जो फिलहाल फरार हैं। यह बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह पूरा मामला पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए छात्र आंदोलनों से जुड़ा है। छात्रों ने देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए थे। आरोप है कि उस वक्त सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता दिखाई, पुलिस ने लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और टॉर्चर जैसी कार्रवाई की। यही आरोप अब मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह शेख हसीना की सत्ता में वापसी की हर संभावना को खत्म कर देगा। वहीं, अवामी लीग पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। हालांकि, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का कहना है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और कानून के तहत निष्पक्ष सुनवाई होगी।

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद बचाव कार्य जारी; सामान्य बारिश में जलस्तर तेजी से बढ़ने की होगी जांच

काठमांडू । नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद गुरुवार को भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है। नेपाल के रसुवा जिले में बारिश के बाद बाढ़ आई, जिसमें नौ लोगों की मौत हो चुकी है और 19 लोग अभी भी लापता हैं। रसुवा जिले के मुख्य जिला अधिकारी अर्जुन पौडेल ने बताया कि सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है और 150 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। इनमें 127 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इन लोगों को एयरलिफ्ट कर काठमांडू ले जाया गया। पौडेल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाके में बिजली और टेलीफोन सेवाएं बाधित होने से बचाव और अन्य अभियान बाधित हुए हैं। उन्होंने कहा, हम फिलहाल चीन सीमा के जरिए सीमित संचार बनाए हुए हैं। टेलीफोन संपर्क बहाल करने और बिजली आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह आई बाढ़ के बाद लापता हुए 19 लोगों की तलाशी अभियान भी जारी है। लापता लोगों में छह चीनी नागरिक और दो पुलिसकर्मी शामिल हैं। काठमांडू से 120 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित रसुवा जिले में आई बाढ़ में नेपाल को चीन से जोड़ने वाला मैत्री पुल भी बह गया है। साथ ही रसुवागढ़ी जलविद्युत संयंत्र और नेपाल-चीन सीमा के पास स्थित ड्राई पोर्ट का कुछ हिस्सा भी बाढ़ में बह गया है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बाढ़ में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शवों का महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। एक शव की पहचान हो गई है और बाकी की पहचान की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) के महानिदेशक दिनेश भट्ट के अनुसार, यह बाढ़ नेपाल-चीन सीमा के पास स्थित एक हिमनद झील के फटने के कारण आई हो सकती है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हालांकि, हम विशेषज्ञों की मदद से आपदा के वास्तविक कारण का अध्ययन कर रहे हैं। पर्याप्त वर्षा के बिना भी जल स्तर एक समय 3.5 मीटर तक बढ़ गया था, जो असामान्य है।